



**कार्यालय—अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।**

E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com,

Phone/Fax: 0135 2767611

G2
मार्च 2023 INDIA

पत्रांक— 2318 / FP/UK/ROAD/147686/2021: देहरादून: दिनांक: ३ अप्रैल, 2023
सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-मध्य क्षेत्र),
25 सुभाष रोड, देहरादून।

विषय :—जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य के सहारनपुर जिले में, दिल्ली—सहारनपुर—देहरादून आर्थिक गलियारे (ग्राम हरगोवा) से शुरू होकर उत्तराखण्ड राज्य के हरिद्वार जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग—334 के बहादराबाद बाईपास (ग्राम आतमलपुर—बौंगला) तक 6लेन अमिगम नियन्त्रित हरिद्वार के लिए स्पर का उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड राज्य में भारतमाला परियोजना अन्तर्गत विकास के किमी 0 19.060 से किमी 0 50.700 तक राजमार्ग निर्माण हेतु 1.6535 है 0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्रत्यावर्तन। (Online No. FP/UK/ROAD/147686/2021)

सन्दर्भ:—भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र संख्या 8वी/यूसी०पी०/०६/४७/२०२२/एफ०सी०/१४४५, दिनांक 25.01.2023

महोदय,
भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के सन्दर्भित पत्र द्वारा विषयांकित प्रकरण में 26 बिन्दुओं पर स्थिति स्पष्ट करने हेतु सूचना चाही गई थी। जिसका निराकरण कर वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून के सन्दर्भित पत्र संख्या—2143/12-1, दिनांक 15.03.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सहमति की गई है कि वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी। भारत सरकार द्वारा चाही गई सूचना की बिन्दुवार आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गई। भारत सरकार द्वारा चाही गई सूचना की बिन्दुवार आख्या निम्न प्रकार है—

क्र०	शर्त	अनुपालन आख्या
स०		
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या—2143/12-1, दिनांक 15.03.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सहमति की गई है कि वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी। (संलग्नक—1)
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी। (संलग्नक—2)

3. प्रतिपूरक वनीकरण:

क	वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर कुल 3.3077 है 0 कोटावाली क०स० 09. चिड़ियापुर रेंज पर प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यवहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लाटेशन से बचे तथा प्रतिपूरक वृक्षारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षों के अदर पूर्ण किया जाना चाहिए।	वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या—2143/12-1, दिनांक 15.03.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 3.3077 है 0 अवनत वन भूमि कोटावाली के क०स०—09 चिड़ियापुर रेंज पर प्रतिपूरक वनीकरण हेतु धनराशि जमा कर दी गई है तथा वन विभाग द्वारा 3.3077 है 0 अवनत वन भूमि कोटावाली के क०स०—09 चिड़ियापुर रेंज पर प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा वन विभाग द्वारा जहां तक व्यवहारिक हो स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाएगा तथा प्रजातियों की एकल प्लाटेशन से बचा जायेगा। (संलग्नक—3क)
ख	वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या—2143/12-1, दिनांक 15.03.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है। वन मंडल अधिकारी द्वारा

ग	<p>प्रत्यावर्तित किए जाने वाले क्षेत्र की केंद्रमण्डल फाइल, सीए क्षेत्र प्रस्तावित एसओएम०८ी कार्य, प्रस्तावित कैचमेट एरिया ट्रीटमेंट क्षेत्र और डब्ल्यूएल०८०८ी क्षेत्र को लीनियर परियोजनाओं के लिए कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई-ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।</p>	<p>अतिरिक्त प्रमाण पत्र प्रेषित है। (संलग्नक-०३)</p> <p>वन संरक्षक, शिवालिक वृत्ति, उत्तराखण्ड, दृहरादून के पत्र संख्या-2143/12-1, दिनांक 15.03.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रत्यावर्तित किए जाने वाले क्षेत्र की केंद्रमण्डल फाइल, सीए क्षेत्र प्रस्तावित एसओएम०८ी कार्य, प्रस्तावित कैचमेट एरिया ट्रीटमेंट क्षेत्र और डब्ल्यूएल०८०८ी क्षेत्र को लीनियर परियोजनाओं के लिए कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई-ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया गया है। (संलग्नक-३)</p>
४	<p>प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रवतित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तम्भन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अधिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुशित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्राक्घान शामिल किए जा सकते हैं।</p>	<p>वन संरक्षक, शिवालिक वृत्ति, उत्तराखण्ड, दृहरादून के पत्र संख्या-2143/12-1, दिनांक 15.03.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त के अनुपालन के संबंध में सहमति व्यक्त करते हुए वचनवद्धता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसकी मूल प्रति रालग्न है। (संलग्नक-४)</p>
५	<p>शुद्ध वर्तमान मूल्य</p> <p>इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(c) संख्या. 202/1995 में IAनंबर 566 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ.री. (P12) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006- एफ.री. दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3/ 2007-एफ.री. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 1,6535 हेठो वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।</p>	<p>क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण (Compensatory Afforestation) एवं उनके 10 वर्षों के रख-रखाव हेतु अकन रु0 13,49,230/- की घनराशि एवं अधिरोपित शर्त के अनुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि 1,6535हेठो का कुल वर्तमान मूल्य (Net Present Value (NPV))अकन रु0 15,83,689/-, कुल अकन रु0 29,32,919/- (13,49,230+15,83,689) घनराशि सम्बन्धित खाते में RTGS के माध्यम से जमा की जा चुकी है। (RTGS copy enclosed) (संलग्नक-५)</p>
६	<p>विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।</p>	<p>सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा देय होगा। (संलग्नक-५)</p>
७	<p>प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा जोकि प्रस्ताव के अनुसार 285 trees and 01 sapling से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।</p>	<p>प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा एवं प्रमाणित होने वाले वृक्षों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 285 trees and 01 sapling वृक्षों से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी। (संलग्नक-६)</p>
८	<p>गाईडलाइन्स में दिए गए दिशानिर्देशों के पैसा 112 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति आपको प्रेषित की जायेगी। वन विभाग द्वारा इसकी कटाई से निगरानी करेगी तथा सुनिश्चित करेगी कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश की तिथि से 01 वर्ष की समाप्ति तक उल्लिखित कार्यों के अलावा कोई अन्य गतिविधि नहीं की जाएगी।</p>	<p>उक्त के सम्बन्ध में गाईडलाइन में दिये गये दिशानिर्देशों के पैसा 112 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिये पारित किये गये आदेश की प्रति आपको प्रेषित की जायेगी। वन विभाग द्वारा इसकी कटाई से निगरानी करेगी तथा सुनिश्चित करेगी कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश की तिथि से 01 वर्ष की समाप्ति तक उल्लिखित कार्यों के अलावा कोई अन्य गतिविधि नहीं की जाएगी। (संलग्नक-७)</p>
९	<p>State Govt. is requested to upload the digital map in online Part-I, which showing forest and</p>	<p>प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा डिजिटल मैप में वन भूमि एवं वन भूमि को अलग-अलग रंग से प्रदर्शित कर ऑनलाइन भाग-। में अपलोड</p>

	non-forest areas with different colours.	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (https://Parivesh@nic.in) के माध्यम से क्षतिपूरक बनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फँड में स्थानांतरित जगा किए जाएंगे।	कर दिया गया है। (संलग्नक-8)
9	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (https://Parivesh@nic.in) के माध्यम से क्षतिपूरक बनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फँड में स्थानांतरित जगा किए जाएंगे।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त के अनुपालन के साथ में सहमति घटक करते हुए वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। मूल प्रति (संलग्नक-9)	
10	एफआरए 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	वन विभाग द्वारा एफ0आर0ए0-2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा। (संलग्नक-10) (1 से 3)	
11	नवीनतम वन (सरकारी) नियम 28.06.2022 के अनुसार, पांचवे वर्ष में न्यूनतम कैगोपी धनत्व कम से कम 0.4 होनी चाहिए और परिपक्व वृक्षारोपण(mature plantation) में वनस्पति धनत्व कम से कम 0.7 होना चाहिए।	मान्य है। (संलग्नक-11)	
12	वन मण्डल अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण के रथलों को विना संक्षम अधिकारी के अनुमोदन के रवेचानुसार नहीं बदलेंगे।	परियोजना के अन्तर्गत प्रमावित सरकारी वन भूमि के राष्ट्रक्ष सिन्हीत की गई क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु अवनत वन भूमि का स्थल नहीं बदला जायेगा। (संलग्नक-12)	
13	नोडल अधिकारी, State CAMPA यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण स्कीम के अनुसार बजाट वन मण्डल अधिकारी को उपलब्ध करवायेंगे।	मान्य है। (संलग्नक-13)	
14	पर्यावरण (सरकारी) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय रथीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	उक्त परियोजना के तहत पर्यावरण (सरकारी) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय रथीकृति प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय रथीकृति लागू नहीं है। (संलग्नक-14)	
15	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट द्वान नहीं बदला जाएगा।	प्रयोक्ता विभाग द्वारा केंद्र सरकार पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट द्वान नहीं बदला जाएगा। (संलग्नक-15)	
16	वन भूमि पर कोई भी अभिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	वन विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों हेतु किसी अभिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा। (संलग्नक-16)	
17	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषत वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।	वन विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वैकल्पिक ईंधन प्रयोक्ता अभिकरण को मजदूरों हेतु किसी अन्य कानूनी स्रोत प्रर्याप्त लकड़ी विवेशत वैकल्पिक दिया जाएगा। (संलग्नक-17)	
18	सम्बित वन मण्डल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तीत वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आरसीसी पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward Backward bearings अंकित हो।	सम्बित वन मण्डल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तीत वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आरसीसी पिलर्स द्वारा सीमांकन कर दिया गया है। (संलग्नक-18)	
19	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	वन विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि परियोजना अभिकरण द्वारा परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा। (संलग्नक-19)	
20	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	वन विभाग द्वारा यह सुनिश्चित / निगरानी की जायेगी कि परियोजना अभिकरण प्रयोक्ता द्वारा वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी परियोजना हेतु नहीं किया जायेगा। (संलग्नक-20)	
21	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जाएगी।	राज्य सरकार द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जाएगी। (संलग्नक-21)	

22	प्रत्ये राजकार द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि केवल राजकार की पूर्णमति के बिना प्रत्यावर्तित हेतु प्रत्यावर्ति वन मृगे किसी भी परिवर्तन में किसी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को उत्पात्तरित नहीं कराएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त किसी भी शर्त उल्लंघन नहीं किया जायेगा। (संलग्नक-22)
23	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन गंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के लित में समय-समय पर निर्धारित शर्तों लागू होंगी।	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन गंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के लित में समय-समय पर निर्धारित शर्तों लागू होंगी। (संलग्नक-23)
24	प्रयोक्ता अभिकरण गलवा निरतारण योजना के अनुराग फूलगिरिपट खण्डों पर इस प्रकार गलवे का निरतारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तथा रीमा से नीये न गिरे प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में परियोजना की लागत पर उपयुक्त प्रजातियों के पौधों लगाकर गलवा निरतारण क्षेत्र को रिथर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा गलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारों का निर्माण किया जायेगा निरतारण रथलों के राज्य के वन विभाग को राँपने से पूर्व इनका रिथरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार रामयवद्ध तरीके से पूर्ण किया जायेगा। (संलग्नक-24)	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पूर्वविदिष्ट रथलों पर इस प्रकार मलवे का निरतारण किया जायेगा। कि वह अनावश्यक रूप से तथा रीमा से नीये न गिरे प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में परियोजना की लागत पर उपयुक्त प्रजातियों के पौधों लगाकर गलवा निरतारण क्षेत्र को रिथर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा गलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारों का निर्माण किया जायेगा निरतारण रथलों के राज्य के वन विभाग को राँपने से पूर्व इनका रिथरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार रामयवद्ध तरीके से पूर्ण किया जायेगा। (संलग्नक-24)
25	यदि कोई अन्य राज्यमिति अधिनियम / अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश / अनुदेश आदि इस प्रताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरुरी अनुमति लेना राज्य राजकार/ प्रयोक्ता एजेंसी की जिमोवारी होगी।	राज्य राजकार एवं प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस प्रताव में लागू होने वाले अधिनियम / अनुच्छेद / नियम / न्यायालय समस्त आदेश / अनुदेश के अधीन जरुरी अनुमति प्राप्त कर ली गई है। (संलग्नक-25)
26	अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल (https://@parivesh-nic.in) पर अपलोड की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन रिपोर्ट की ई-पोर्टल (https://@parivesh-nic.in) पर अपलोड की जाएगी। (संलग्नक-26)

अतः प्रश्नगत प्रकरण में वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक-2143/12-1, दिनांक-15.03.2023 द्वारा प्रेषित अनुपालन आख्या के क्रम में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें। संलग्न-उपरोक्तानुसार ।

भवदीय,
३०५/२३
(एस०एस०रसाइली)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या : / FP/UK/ROAD/147686/2021 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून को उनके पत्रांक 2143/12-1, दिनांक-15.03.2023 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रभागीय वनाधिकारी, हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार।

(एस०एस०रसाइली)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।